1216 mada. No other schemes have been Тне MINISTER OF

sponsored by the State Government during the Third Plan period so far.

OFFICERS DEPUTED BY THE C.W.P.C. FOR TRAINING ABROAD

- 217 SHRI NIRANJAN SINGH: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:
- (a) how many of the officers who were deputed for training abroad in the year 1962-63 by the Central Water and Power Commission have returned to India: and
- (b) where were they trained, the subjects in which they were trained and the places where they are employed after their return?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): (a) Sixteen

(b) A statement is attached. [See Appendix XLV, Annexure No. 10].

VISIT OF INDIAN BANANA DELEGATION TO MIDDLE EAST

218. SHRI N. SRI RAMA REDDY: Will the Minister of International Trape be pleased to state whether an Indian banana delegation recently visited several countries in the Middle East?

MINISTER THE OF INTERNA-TIONAL TRADE (SHRI MANURHAT SHAH): Yes Sir.

DECISIONS TAKEN AT THE CONFERENCE OF INCOME-TAX COMMISSIONERS

219. SHRI NIRANJAN SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the decisions taken recently at the conference of Commissioners of Income-tax held at Delhi regarding realization of arrears of tax estimated at more than Rs. 175 crores and the evasion of income-tax?

FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI): Conference does not take any decisions. Suggestions were, however, made at the Conference of Commissioners of Income-tax held cently at Delhi regarding the covery of arrears of tax and checking evasion of income-tax. These suggestions will be examined by the Central Board of Revenue and Government in the light of further reports which will be submitted by the Commissioners.

कम्पनियों के ग्राडिट के लिए नियम

२२०. श्री विमलकुमार मन्नालालजी बौरडिया : क्या बित्त मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि दुपतरी-शास्त्री समिति की रिपोर्ट के अनुसार कम्पनियों के आडिट के लिये जो नियम बनाने का सुझाव था, उस के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†[Rules for Audit of Companies

220. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state what progress has so far been made in respect of the proposal to frame rules for the audit of companies in accordance with the Daftary-Sastri Committee Report?]

वित्त मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) मंत्री सम्भवतः शास्त्री समिति की इस सिफारिश का जिक कर रहे हैं कि चार्टर-प्राप्त लेखाकार संस्थान (इंस्टिटयट भ्राफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) की परिषद (कौंसिल) से कहा जाय कि वह उन लोगों के हित की रक्षा का विशेष ध्यान रखते हए सरकारी कम्पनियों की लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में एक संहिता (कोड) तैयार करे जिन्हों ने निदेशक-मण्डल (बोर्ड भ्राफ डायरेक्टर्स) का विश्वास कर के शेयर खरीदे हैं। स्रगर ऐसा है, तो संस्थान की परिषद को यह बात पहले ही बता दी गयी

^{†[]} English translation.

1218

है। परिषद की एक उप-समिति ने संहिता का मसविदा भी तैयार कर लिया है जिस में उन सिद्धान्तों को शामिल किया गया है जिन के अनुसार लेखा परीक्षकों को आम बौर से कम्पनियों के लेखे की जांच करनी चाहिये। यह मसविदा परिषद् के मदस्यों के विचार जानने के लिये उन के पास भेज दिया गया है। उन विचारों के आधार पर संहिता को अन्तिम रूप दिया जायगा और तब उसे परिषद् के कार्य करने वाले सभी सदस्यों के पास उन के मार्गदर्शन के लिए भेज दिया जायगा।

†ITHE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI): The Hon'ble Member is presumably referring to the recommendation of the Daftary-Sastri Committee that the Council of the Institute of Chartered Accountants should be called upon to formulate a code in regard to the audit of the accounts of public companies with special reference to safeguarding the interests of members of the public who have put their faith in the board of directors and contributed to the share capital. If this is so, the Council of the Institute is already seized of the matter. A sub-Committee of the Council has since prepared a draft embodying the principles which should generally be followed by the auditors in auditing the accounts of companies. The draft has been circulated to the members of the Council for comments. In the light of these comments, this code will be finalised and issued to all practising members of the Institute for their guidance,]

ग्रफीम की कारत के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी नियमों में संशोधन

२२१. श्री विमलकुमार मञ्जलालजी मौरड़िया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले पांच वर्षों में अफीम की काश्त के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के क्या प्रयोजन थे ; ग्रौर
- (ख) ये संशोधन किस किस तारीख को किये गये ?

†[Amendment of Rules relating to GRANT OF LICENCES FOR POPPY CULTIVATION

221. Shri V. M. CHORDIA: Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) the purpose for which the rules relating to the grant of licences for poppy cultivation were amended during the last five years; and
- (b) the dates on which these amendments were made?]

वित्त मंत्री (श्री टो० टी० कृष्णमाचारी)

- (क) पोस्त की काश्त के लिए श्राइसेंस देने की नीति पर हर साल इसलिए विचार करना पड़ता है कि आवश्यकता के अनुसार खेती के आवश्यक क्षेत्र के लिये श्राइसेंस दिये जा सकें। ऐसा करते हुए इस ब्रात का प्रयत्न भी किया जाता है कि नीचे विये गये उपायों द्वारा उपज के गैर-कानूनी तौर से हटाये जाने के खतरों को कम किया जा सके और औसत उपज में ज्यादा से ज्यादा बृद्धि की जा सके :—
 - (१) श्रकुशल खेतिहरों ग्रौर श्रनुत्पादक भिम को श्रलग करना ।
 - (२) कास्त को एक दूसरे से लगे हए क्षेत्रों तक सीमित रखना ।
 - (३) कम खर्चीले श्रौर ज्यादा श्रच्छे नियंत्रण के लिए उपयुक्त स्थिति पैदा करना ।
- (ख) लाइसेंस जारी करने के सिद्धान्तों क्री सूचना नशीली वस्तु सम्बन्धी श्रायुक्त